माफिया सरदार ठाकरे को सजा कौन देगा ?

महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और उनके चाचा शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश से रेलवे की परीक्षा देने गये छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बिहार के दो नवयुवकों और उत्तर प्रदेश से नौकरी की तलाश में मुंबई गये एक युवक की हत्या की गई, इसकी प्रतिक्रिया होनी ही थी। मनसे और शिवसेना की इस खुली गुंडागर्दी का ही यह परिणाम है कि 9 नवम्बर को पटना में आयोजित होने वाली रेलवे की परीक्षा स्थगित कर दी गई। बताया जाता है कि इस परीक्षा में काफी संख्या में मराठी प्रत्याशी भाग लेने वाले थे। राज ठाकरे और बाल ठाकरे द्वारा हिंदीभाषियों के खिलाफ जो हिंसा भड़काई गई, उसे देखते हुए प्रतिक्रियास्वरूप बिहार में भी मराठीभाषियों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाने लगे, इस आशंका के कारण ही रेल मंत्री लालू प्रसाद ने पटना में परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया। दुबारा भी यह परीक्षा स्थगित की गई। लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। रेलवे और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं का केन्द्र पटना रहता आया है जहां देश के कई प्रांतों से परीक्षार्थी आते रहे हैं। लेकिन जब-जब बिहार के छात्र खासकर रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र गये तो वहां उन्हें शिवसेना के गुंडों ने अपना निशाना बनाया। अब राज ठाकरे अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने बिहार के श्रमिकों को महाराष्ट्र से भगाने का आतंकवादी अभियान चलाया था। परिणामस्वरूप लाखों की संख्या में बिहार के मजदूर रोजी-रोटी छोड़कर वहां से भागने पर विवश हुए। इसका विरोध महाराष्ट्र के फैक्ट्री मालिकों ने किया, क्योंकि बिहारी मजदूरों और तकनीशियनों के पलायन से उनके उत्पादन पर असर पड़ा व उन्हें घाटे का सामना करना पड़ा। पर राज ठाकरे को इसकी परवाह भला क्यों हो? उनकी गुंडागर्दी हर सीमा को पार करती चली गई और महाराष्ट्र की कांग्रेस व राष्ट्रवादी गठबंधन सरकार मूक दर्शक बनी रही। राज ठाकरे और उनके गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस विलासराव देशमुख की सरकार नहीं कर पाई, परिणामस्वरूप राज ठाकरे का दु:साहस बढ़ता ही चला गया।

बिहारियों को महाराष्ट्र से भागने पर मजबूर कर देने के बाद राज ठाकरे ने भाषावाद की राजनीति शुरू की। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई महानगर में उन्होंने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साइनबोर्ड जबरन मराठी में लिखवाने लगे। इसका व्यवसाइयों ने विरोध किया। पर राज ठाकरे के गुंडों के आगे उनकी एक भी नहीं चल पाई। वे तो बेचारे पहले जहां सिर्फ शिवसेना को ही चौथ देते थे, अब उन्हें राज ठाकरे की सेना को भी चौथ देना पड़ रहा है। लेकिन वे करें तो क्या करें? मुंबई माफिया सरदारों और गॉड फादरों का शहर है। यहां जितने भी माफिया हैं, उनमें शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे सबसे बढ़-चढ़ कर हैं। इनके बाद राज ठाकरे का नम्बर आता है। दाऊद इब्राहीम, छोटा राजन और गांधी टोपी पहनने वाला माफिया सरदार अरुण गवली की ताकत भी इनसे कम है। ये शासन और सत्ता द्वारा पकड़े जाने के भय से पूर्णत: मुक्त हैं और आतंक का राज चलाते हैं।

बिहारियों को महाराष्ट्र से भागने पर मजबूर कर देने के बाद राज ठाकरे ने भाषावाद की राजनीति शुरू की। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई महानगर में उन्होंने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साइनबोर्ड जबरन मराठी में लिखवाने लगे। इसका व्यवसाइयों ने विरोध किया। पर राज ठाकरे के गुंडों के आगे उनकी एक भी नहीं चल पाई। वे तो बेचारे पहले जहां सिर्फ शिवसेना को ही चौथ देते थे, अब उन्हें राज ठाकरे की सेना को भी चौथ देना पड़ रहा है। लेकिन वे करें तो क्या करें? मुंबई माफिया सरदारों और गॉड फादरों का शहर है। यहां जितने भी माफिया हैं, उनमें शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे सबसे बढ़-चढ़ कर हैं। इनके बाद राज ठाकरे का नम्बर आता है। दाऊद इब्राहीम, छोटा राजन और गांधी टोपी पहनने वाला माफिया सरदार अरुण गवली की ताकत भी इनसे कम है। ये शासन और सत्ता द्वारा पकड़े जाने के भय से पूर्णत: मुक्त हैं और आतंक का राज चलाते हैं।

राज ठाकरे की गुंडागर्दी की जब देशव्यापी आलोचना शुरू हुई और केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के प्रमुख नेता लालू प्रसाद, रामविलास पासवान और रघुवंश नारायण सिंह ने विरोध का स्वर बुलंद किया एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर राज ठाकरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की तो विलासराव देशमुख सरकार की पुलिस ने राज ठाकरे और उनके समर्थकों की प्रतीकात्मक गिरफ्तारी की। दो दिन के भीतर ही उन्हें छुट्टा घूमने और समाज में प्रांतवाद व भाषावाद का विषवमन करने के लिए जमानत पर छोड़ दिया गया, जबकि उनके अपराधपूर्ण गतिविधियों को देखते हुए जमानत हरगिज नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने गुंडों के इस सरदार को परोक्ष समर्थन प्रदान कर रखा है। मराठा सरदार कहे जाने वाले कृषि मंत्री शरद पवार के शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से अत्यंत ही मधुर संबंध हैं। भाजपा नेतृत्व जहां एक तरफ राज ठाकरे की गुंडागर्दी का विरोध करता है, वहीं शिवसेना के बचाव में आ जाता है, पर लोगों को अच्छी तरह से पता है कि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी विचारधारा और कार्यशैली में कोई अंतर नहीं है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी इनके खिलाफ प्रभावी व ठोस कार्रवाई कर पाने में असमर्थ है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शर्मो-हया त्याग कर यह स्वीकार कर लिया है कि वे इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। सोनिया गांधी ने तो इस मुद्दे पर मुंह ही नहीं खोला। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या महाराष्ट्र ठाकरे परिवार की जागीर है?

महाराष्ट्र में मनसे और शिवसेना के गुंडों ने न सिर्फ बिहार, बल्कि उत्तर प्रदेश के नवयुवकों के साथ भी हिंसात्मक व्यहार किया। इससे क्रुद्ध होकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने भी महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी।

बिहार में तो इसकी उग्र प्रतिक्रिया हुई। आक्रोशित छात्रों-युवकों ने कई दिनों तक मुंबई व दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का परिचालन बाधित कर दिया। छात्रों-युवकों के उग्र विरोध के कारण प्रशासन को कई शहरों में धारा-144 लगानी पड़ी।

एक मराठी महिला आईएएस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश भी की गई, पर बिहार सरकार ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि वहां रह रहे मराठीभाषी लोगों के साथ दुर्व्यवहार न हो। ऐसे भी बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य हिंदी भाषा भाषी राज्यों में प्रांतवाद व भाषावाद के नाम पर राजनीति नहीं चलती।

बिहार के लोगों के साथ कई राज्यों में दुर्व्यवहार किया जाता है व उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जाती है। पर बिहार में दूसरे प्रांत के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया गया हो, इसका उदाहरण शायद ही मिले। लेकिन प्रतिक्रियावादी तत्व हर जगह हैं। अगर वे राज ठाकरे व बाल ठाकरे की आतंककारी गतिविधियों के खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू कर दें तो दंगे भड़क सकते हैं। हिंदी भाषी राज्यों में रहने वाले मराठियों पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होगा। इस बात को राज ठाकरे व बाल ठाकरे जैसे माफिया सरदार क्यों नहीं समझ पाते? अभी भी ये शातिर और बदमाश लोग यह कह रहे हैं कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ बढ़ने का कारण बिहार और यू.पी. के लोगों का इन ट्रेनों से आना-जाना है। क्या मुंबई में चलने वाली लोकल ट्रेनें सिर्फ मराठियों के लिए आरक्षित होंगी?

बावजूद इसके अभी तक किसी हिंदी भाषी राज्य में मराठियों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात नहीं हुई है। पर मराठी डरे हुए हैं। उनका डरना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए हरियाणा में महाराष्ट्र के 15,000 परिवार रहते हैं। पिछले दिनों करनाल में एक मराठी परिवार के यहां तीन हथियारबंद लोग प्रवेश कर गये और उन्हें राज्य छोड़कर जाने अथवा यहां रहने पर बुरा परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। गत 15 वर्षों से शांतिपूर्वक करनाल में अपना व्यवसाय चलाने वाला वह परिवार यहां से बोरिया-बिस्तर समेटने की तैयारी करने लगा। पर इस मामले के मीडिया में उछल जाने के कारण प्रशासन ने उस परिवार को यहां बने रहने के लिए राजी कर लिया। उस परिवार का यह मानना है कि हरियाणा में उनके साथ लोगों ने बराबर अच्छा व्यवहार किया। कभी भी उन्हें अपमानित नहीं किया गया।

राज ठाकरे और शिवसेना द्वारा उत्तर भारतीयों के खिलाफ चलाये गये अभियान के प्रतिक्रियास्वरूप बिहार और यू.पी. के लोगों के एक संगठन - यादव समाज ने हरियाणा और पंजाब से मराठियों को भगाने की योजना तैयार की है। उन्होंने पंजाब के नया गांव में एक बैठक कर चंडीगढ़ पंचकूला एवं मोहाली में रह रहे 3-4000 मराठियों को भगाने का निर्णय लिया है। पर सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। इधर महाराष्ट्र मंडल के प्रतिनिधियों ने चंडीगढ़ के एस.एस.पी. से मुलाकात कर मराठियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। लेकिन अखिल भारतीय यादव समाज की गतिविधियां जारी रहीं तो घृणा का जहर फैलता चला जायेगा। और इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार होगा तो सिर्फ राज ठाकरे एवं बाल ठाकरे व इनके खिलाफ कार्रवाई न करनेवाली महाराष्ट्र की कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन सरकार। केंद्र सरकार भी इसके लिए कम दोषी नहीं है। केंद्र सरकार ने देश को विभाजित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया।

वैसे, हिंदी भाषी राज्यों में रहने वाले मराठियों के खिलाफ लोगों द्वारा किसी तरह का कदम उठाना बहुत ही गलत होगा। उनका कोई दोष नहीं है। अपराधी तो है राज ठाकरे और बाल ठाकरे। कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। इन माफिया सरदारों को मराठियों की भी कोई परवाह नहीं है। इन्हें परवाह है सिर्फ सत्ता की। ये किसी भी भांति सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, भले ही इसके लिए इन्हें निरपराध लोगों की जान से भी खेलना पड़े।

यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार इन माफिया तत्वों के खिलाफ स्वार्थ के वशीभूत हो कार्रवाई नहीं करना चाहती। अत: अब आम जनता को ही इनके खिलाफ संगठित होकर उतरना होगा और इन्हें इनके द्वारा किये गये दुष्कर्मों की सजा देनी होगी।

■ मनोज कुमार झा

पृष्ठ 4 का शेष

एक किसान...

किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई है। लेकिन ऐसी किसी तुलना से हम वास्तविकता को नहीं समझ सकते। यदि रहट के जमाने से आज की तुलना करें तो यह भी देखना होगा कि उस जमाने में राजा भी हाथी-घोड़े की कष्टप्रद सवारी करते थे। उनके पास भी आज की तरह तेज रफ्तार मोटर गाड़ियां और सुपर सोनिक विमान नहीं थे। गंभीर बीमारियां सभी के लिए लाइलाज थीं। किसानों के घरों में यदि तेल की डिबिया जलती थी तो महलों में भी मशालों से ही रोशनी होती थी। बीते जमाने की तुलना आज के समय से करना हास्यास्पद है। अगर इस प्रकार असंगत तुलना करेंगे तो आदिम युग के गुफा मानव तुलना में आज का भिखारी भी धनी दिखाई देगा जिसके पास एक जोड़ी कपड़े और एक कटोरा होता है।

किसानों की वास्तविक स्थिति का सही अनुमान देश के बाकी वर्गों से तुलना करके ही लगा सकते हैं। आज इन्सान के व्यक्तित्व का विकास करने वाले इतने साधन और ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं कि आदमी समुद्र की अतल गहराइयों की रहस्यमय दुनिया को अपनी आंखों से देख सकता है। पर्वतों की बर्फीली चोटियों पर बर्फ को छू सकता है। एक तरफ करोड़ों रुपये खर्च कर लोग अन्तरिक्ष की सैर करने जा रहे हैं, उसी युग में एक किसान के लिए क्यों दुनिया उतनी ही दूर तक है जहां उसके रिश्तेदार बसते हैं या जहां वह भैंस खरीदने जा सकता है। जिस युग में एक ओर कुछ लोग पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, स्कीईंग जैसे नए-नए खेलों का आनन्द लेते हैं, उसी युग में किसान के बेटों के जीवन से कुश्ती, कबड्डी और बॉलीबॉल जैसे ग्रामीण खेल भी गायब होते जा रहे हैं। उनकी दुनिया में मनोरंजक गतिविधियां साढ़े छ: मिनट में 1600 मीटर दौड़, तेरह फुट लम्बी और पौने चार फुट ऊंची कूद तक ही सिमट कर रह गई हैं।

तुलना तो इस बात से की जानी चाहिए कि इन्सान के जीवन को आसान बनाने वाली जो नई-नई चीजें बन रही हैं, उनकी किसानों को भी उतनी ही जरूरत है जितनी बाकी लोगों को, लेकिन किसान की आमदनी दिनों-दिन घटती चली जा रही है। यानी समाज के विकास के अनुरूप किसानों की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास नहीं हो पाया है। तुलना इस तरह भी की जानी चाहिए कि दुनिया की सारी सुविधाओं का उपयोग करने वाले और जनता को सन्तोषम् परमम् सुखम् का उपदेश देने वाले लोगों को यदि दस दिन भी यदि इन हालतों में जीना पड़े तो क्या उनके लिए किसानों का जीवन किसी बामशक्कत कैद से कम होगा?

लेकिन हम यह भी जानते हैं कि दुनिया की विकास-यात्रा का कोई अन्त नहीं है। दुनिया के इतिहास में ऐसी मिसालें भी हैं जब किसानों ने दूसरे मेहनतकश वर्गों के साथ मिलकर अपने कन्धों से शोषण का जुआ उतार फेंका और इंसान के रूप में शानदार जिन्दगी जीने का हक हासिल किया। जरूरत इस बात की है कि हम सपने देखें और उन्हें साकार करने के प्रयास में लग जायें।

■ संजीव, अभिलाष